



Helpline

1064



94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- झुंझुनूं में पुलिस थाना मुकुन्दगढ़ का कानिस्टेबल 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी

जयपुर, 17 मार्च, शुक्रवार / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर सीकर इकाई द्वारा आज झुंझुनूं में कार्यवाही करते हुये बलबीर सिंह कानिस्टेबल पुलिस थाना मुकुन्दगढ़, जिला झुंझुनूं को परिवादी से 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की सीकर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में कार्यवाही करने की एवज में बलबीर सिंह कानिस्टेबल पुलिस थाना मुकुन्दगढ़, जिला झुंझुनूं द्वारा 20 हजार रुपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कालूराम रावत के सुपरवीजन में एसीबी सीकर इकाई के उप अधीक्षक पुलिस श्री राजेश जांगिड़ द्वारा शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज पुलिस निरीक्षक श्री सुरेश चंद द्वारा मय टीम के आज झुंझुनूं में ट्रैप कार्यवाही करते हुये बलबीर सिंह पुत्र श्रीराम निवासी ग्राम डेरवाला, तहसील व जिला झुंझुनूं हाल कानिस्टेबल पुलिस थाना मुकुन्दगढ़, जिला झुंझुनूं को परिवादी से 10 हजार रुपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी कानिस्टेबल द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान भी परिवादी से 10 हजार रुपये रिश्वत राशि जरिये फोन-पे वसूल कर ली थी।

एसीबी के महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाईन नं. 1064 एवं WhatsApp हैल्पलाईन नं. 94135-02834 पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।